भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं.229**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

फ्रेट स्मार्ट सिटीज़

***229. डॉ. सुकान्त मजूमदार :**
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने शहरों में माल ढुलाई व्यवस्था की दक्षता में सुधार करने तथा संभार-तंत्र संबंधी लागतों में कमी लाने के लिए अवसर सृजित करने के लिए 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' को विकसित करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शहरी माल ढुलाई व्यवस्था में सुधार करने हेतु 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' संबंधी वेबसाइट भी आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' के रूप में विकसित किए जाने के लिए आरंभ में दस शहरों की पहचान करने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' विषय पर दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 229 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : वर्तमान में सरकार देश में फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के विकास की संभावना को तलाशने के लिए राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, तकनीकी संस्थानों, आदि के साथ स्टेकहोल्डर विचार-विमर्श कर रही है।

(ख) : जी, हां। वेबसाइट में अवधारणा, संसाधन तथा दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई है।

(ग) : राज्य सरकारों से फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित किए जाने के लिए शहरों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श के दौरान एक इनपुट यह रहा कि इसे ऐसे 10 शहरों की सूची के साथ आरंभ किया जाए, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) : शहरी फ्रेट में सुधार लाने के लिए राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित रूप से अलग-अलग उपाय किए जाते हैं। सरकार ने संबद्ध एवं सुनियोजित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शहरों को सुरक्षित तथा और अधिक रहने योग्य बनाकर शहरों के लॉजिस्टिक्स में सुधार करने के लिए राज्यों, तकनीकी संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विभिन्न स्टेकहोल्डर वार्ताएं की हैं। *'इन्हान्सिंग अर्बन फ्रेट सिस्टम्स'* संबंधी एक मार्गदर्शी दस्तावेज जिसमें शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 14 प्रमुख सुझाए गए उपायों को दिया गया है, को राज्यों के साथ 2 जुलाई, 2021 को साझा किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दक्ष शहरी माल ढुलाई पर फरवरी, 2019 में एक विचार-विमर्श पत्र शुरू किया है जिसमें तीन दस्तावेज अर्थात् नीति रूपरेखा, नीति वर्कबुक तथा आकलन मैट्रिक्स हैं।

******